



भारत का यजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

मं. 426] मई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 24, 1976/आश्विन 2, 1898

No. 426] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 24, 1976/ASVINA 2, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न वी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 24th September 1976

S.O. 635(E)/18FB/IDRA/76.—Whereas by the order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 547(E)/18FB/IDRA/75 dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that—

- (a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertaking known as Messrs. Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta; and
- (b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it immediately before the date of publication of that Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the Central Government is satisfied that the said Order should be extended for a further period of one year;

(1869)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 26th September, 1977.

[No. F.2/28/75-CUC]
A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(शैक्षणिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली 24 सितम्बर, 1976

का० आ० 635 (अ) / 18 चख/उ० वि० वि० प्र०/76.—भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग श्रीर नागरिक पूर्ति मंत्रालय (शैक्षणिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 547 (अ) / 18 एक बी०/प्राई० डी० आर० ए० / 75 तारीख 27 सितम्बर, 1975 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास श्रीर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित किया था कि—

- (क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमतियाँ मैसर्स सेन एण्ड परिणत इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता, नामक शैक्षणिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी, और
- (ख) ऐसी सभी प्रबुत्त संविदाओं, सम्मति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, समझौतों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों जिनका उक्त शैक्षणिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठीक पूर्व उसे लागू होती हों, का प्रवर्तन और उक्त तारीख से पूर्ण तदृधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारी, विधायाधिकार, बाध्यतायें और दायित्व 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेंगे ;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ;

अतः, अब, उद्योग (विकास श्रीर विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की, उपधारा, (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त आदेश की अवधि 26 सितम्बर, 1977 तक बढ़ाती है।

[सं० का० 2/28/75-सी० पू०सी०]
ए० के० घोष, अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976